सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार
समाचार पत्र में
नियमित पाठक बनने,
समाचार की प्रति
मंगवाने व विज्ञापन
देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं.
9928078717

○वर्ष-23 ○अंक-271 ○दैनिक प्रभात संस्करण ○ जयपुर, गुरूवार 05 जून , 2025 ○पृष्ठ-4 ○मूल्य: 2.50

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर 5 से 20 जून तक चलेगा

'वंदे गंगा' जल संरक्षण-जन अभियान

जयपुर,। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारणवश राजस्थान के कई क्षेत्रों में जल की कमी की समस्या बनी रहती है। भूजल स्तर के तेजी से घटने के साथ ही जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। इस पानी की कमी को दूर करने के लिए जल संरक्षण अतिआवश्यक है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशभर में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान की महत्वपूर्ण पहल की है। विश्व पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशहरा (5 जून) के शुभ संयोग पर शुरू होने जा रहे इस अभियान के अंतर्गत 20 जून तक विभिन्न विभागों द्वारा प्रदेशभर में जल संरक्षण के व्यापक कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इन कार्यों के माध्यम से आमजन को जल संरक्षण की महत्ता के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिससे यह अभियान जन आंदोलन बन सकेगा। इस अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश के 41 जिलों में मंत्रिगणों को नियोजित किया गया है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री करेंगे श्रमदान और पूजन

अभियान के पहले दिन 5 जून को प्रदेशभर में विभिन्न विभागों द्वारा नर्सरियों में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम, तुलसी पौध वितरण, प्लास्टिक का उपयोग कम करने की शपथ, श्रमदान, जल स्रोतों की साफ-सफाई व मरम्मत, वंदे गंगा कलश यात्रा, नदी-बांध-सरोवर का पूजन एवं हरियालो राजस्थान के अंतर्गत पौधरोपण की तैयारी के साथ-साथ कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत कार्यों का अवलोकन एवं स्वीकृति जैसे प्रमुख कार्य किए जाएंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री शर्मा जयपुर के जमवारामगढ़ पर वृक्षारोपण करेंगे। वहीं मोरी के निकट, रामगढ़ बांध पर श्रमदान करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करेंगे।

श्रमदान कीजिए
योगदान दीजिए
वंदे गंगा

इसके बाद मुख्यमंत्री बूंदी के लिए रवाना होंगे जहां वे केशोरायपाटन में मुख्यमंत्री 'वंदे गंगा' जल पूजन, चुनरी महोत्सव एवं कलश पूजन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और समारोह में जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के अंतर्गत बूंदी जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। वे यहां केशवराय भगवान मंदिर में पूजा-अर्चना भी करेंगे। श्री शर्मा शाम को भरतपुर पहुंचेंगे जहां वे गंगा मंदिर में विशेष पूजा और सुजानगंगा में दीपदान भी करेंगे।

निर्जला एकादशी पर होगी वंदे गंगा जल सेवा

निर्जला एकादशी (6 जून) के दिन रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड आदि सार्वजनिक स्थानों पर वंदे गंगा जल सेवा, जल परीक्षण अभियान, जल संरक्षण संरचनाओं की गाद निकालना एवं पशुओं-पक्षियों के लिए साफ पीने के पानी की व्यवस्था के संबंध में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। 7 जून को अभियान पर संगोष्ठियां तथा 8 जून को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर वंदे गंगा प्रभात फेरी और जागरूकता अभियान रैली आयोजित की जाएगी।

9 जून को होगा अमृत सरोवर का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार 9 जून को 11 साल पूरे कर रही है। इस दिन 9 जून को वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार नवीन अमृत सरोवर का शुभारंभ करेगी। साथ ही, नए जल संग्रहण और जल संरक्षण संरचनाओं के कार्यों के शुभारंभ, गांवों के सभी जल स्रोतों की मैपिंग व साफ-सफाई तथा गांवों के मुख्य मार्गों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई आदि पर्यावरण संरक्षण के कार्य भी किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना 2.0 के अंतर्गत होगा नवीन परियोजनाओं का शुभारंभ

अभियान के तहत 10 से 15 जून के मध्य मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के अंतर्गत पूर्ण कार्यों का अवलोकन, मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान 2.2 के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति और प्रारंभ करना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना 2.0 के अंतर्गत नवीन परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार 575 जल संरक्षण संरचनाओं का अवलोकन और मनरेगा के तहत विभिन्न कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही इन दिवसों में किसान चौपाल, डिग्गियों की साफ-सफाई, जल स्रोतों पर दीप प्रज्ज्वलन, प्लास्टिक कचरे का चिन्हित स्थलों पर निष्पादन और अमृत 2.0 के अंतर्गत कार्यादेश जारी करने के कार्य भी प्रस्तावित हैं।

कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का लोकार्पण

इस दौरान जल उपभोक्ता समूहों के कार्यक्रम, कैच द रैन कार्यक्रम और पेयजल स्रोत जैसे ग्राउंड लेवल रिजर्वायर और ऑवर हैड रिजर्वायर की साफ-सफाई की जाएगी। जल बचत हेतु जनजागृति अभियान, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं स्वीकृति, जल उपयोग अंकेषण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता पर निबंध लेखन एवं नुक्कड नाटक आदि गतिविधियों का भी आयोजन भी किया जाएगा।

रात्रि चौपाल में होगी जल संरक्षण पर चर्चा

16 से 19 जून तक अभियान के अंतर्गत चारागाहों का चिन्हिकरण और पौधरोपण की तैयारी, राजीविका के ग्राम संगठन एवं सीएलएफ कार्यालयों में स्वच्छता अभियान के साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत चयनित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि चौपाल आयोजित कर जल संग्रहण एवं संरक्षण पर चर्चा की जाएगी।। साथ ही स्प्रिंकलर, ड्रिप, फार्म पॉण्ड, पाइपलाइन की स्वीकृति, अमृत 2.0 के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा साफ-सफाई कार्यक्रम एवं शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पौधरोपण की अग्रिम तैयारी आदि कार्य किए जाएंगे। 20 जून को अभियान के समापन पर वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के क्रियान्वयन में सहयोग करने वाले भामाशाह एवं संस्थाओं का सम्मान सहित विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं।

डिप्टी CM दीया कुमारी ने मुख्यमंत्री को लिखा खुला पत्र

CM भजनलाल से की ये बड़ी डिमांड

जयपुर। राजस्थान प्रशासनिक सेवा (ङ्क्र) मेन्स परीक्षा 2024 की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर अभ्यर्थियों के हित में विचार करने की अपील की है।

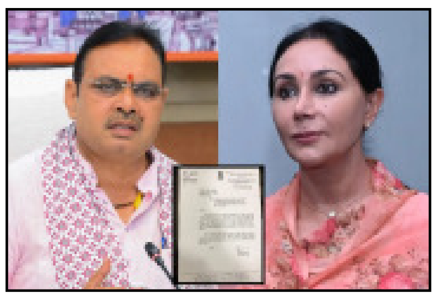

दरअसल, ङ्क्र मेन्स 2024 की परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को प्रस्तावित है। हालांकि, अभ्यर्थियों का कहना है कि RAS 2023 की साक्षात्कार प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और अंतिम परिणाम लंबित हैं। ऐसे में, नई परीक्षा का आयोजन उनके लिए अनुचित हो सकता है, क्योंकि कई अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में शामिल हैं।

दीया कुमारी ने अपने पत्र में क्या लिखा?

दीया कुमारी ने अपने पत्र में लिखा, "RAS 2024 की मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा जाए। ङ्क्र 2023 के परिणाम घोषित होने के बाद ही नई परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि अभ्यर्थियों को उचित समय मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में त्वरित और संवेदनशील निर्णय लेने का अनुरोध किया।

झुंझुनूं में IPL सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश

3 करोड़ का हिसाब और 10 लाख कैश जब्त, तीन गिरफ्तार

झुंझुनूं। राजस्थान में क्रिकेट के खुमार के बीच, झुंझुनूं पुलिस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों पर चलने वाले एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया है। झुंझुनूं पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और कोतवाली थाना पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए तीन प्रमुख आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में ?10,40,350 नकद राशि, 29 मोबाइल फोन सहित सट्टेबाजी में प्रयुक्त होने वाली भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस को आरोपियों से लगभग 3 करोड़ रुपये के सट्टे के लेन-देन का हिसाब-किताब भी मिला है, जो इस रैकेट के बड़े पैमाने पर फैले होने का स्पष्ट संकेत है।

ऐसे हुआ ऑपरेशन का खुलासा

यह बड़ी कार्रवाई झुंझुनूं के कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत के निर्देशानुसार और वृताधिकारी शहर वीरेंद्र कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। मंगलवार, 3 जून की रात को, थाना कोतवाली के उप-निरीक्षक (एसआई) प्यारेलाल अपनी नियमित गश्त पर थे, तभी उन्हें एजीटीएफ प्रभारी विक्रम सिंह से एक पुख्ता सूचना मिली।

सूचना के अनुसार, वसुंधरा नगर स्थित अनिल श्योराण के एक मकान में कुछ लोग पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। सूचना की गंभीरता को समझते हुए, एसआई प्यारेलाल ने तुरंत अपनी टीम के साथ-साथ एजीटीएफ और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) की टीमों को भी बुलाया। सभी टीमें मिलकर बताए गए मकान पर पहुंचीं।

मकान की दूसरी मंजिल से स्पष्ट रूप से क्रिकेट मैच की कमेंट्री और टीवी की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे संदेह और गहरा हो गया। जब पुलिस टीम ने छापा मारा, तो उन्हें तीन व्यक्ति लैपटॉप, रजिस्टर और कई मोबाइल फोन के साथ सट्टेबाजी करते हुए रंगे हाथों मिले। एक मोबाइल फोन से स्पीकर जुड़ा हुआ था, जिससे लगातार सट्टे के भाव बताए जा रहे थे। पुलिस को देखते ही तीनों आरोपी हड़बड़ा गए और प्राथमिक पूछताछ करने पर उन्होंने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाने की बात कबूल कर ली।

करोड़ों का खेल और डिजिटल नेटवक

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनिल कुमार जाट पुत्र अमरचंद (33) निवासी डाबली की ढाणी, जिला चूरू; जितेंद्र जाट पुत्र रामचन्द्र (33) निवासी बिबासर, झुंझुनूं; और इंतजार अली पुत्र एजाज अली (34) निवासी क्यामसर, झुंझुनूं के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक लैपटॉप, चार्जर, कुल 29 मोबाइल फोन, दो कैलकुलेटर, दो एलईडी टीवी, एक स्पीकर मय चार्जर, एक वाईफाई राउटर, दस लाइनदार रजिस्टर, पांच डायरी, एक पेन, एक बिजली का बोर्ड और आठ मोबाइल चार्जर बरामद किए हैं। यह सभी उपकरण सट्टेबाजी के इस डिजिटल नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे।

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाने के लिए विशेष रूप से %जूम ऐप% का उपयोग करते थे। यह ऐप वाईफाई राउटर के माध्यम से संचालित होता था, जिसमें सिम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी। यह मोडस ऑपरेंडी सटोरियों द्वारा पुलिस की पकड़ में आने से बचने और अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पुलिस को लगभग 3 करोड़ रुपये के सट्टे के लेन-देन का विस्तृत हिसाब मिला है, जो इस रैकेट की व्यापकता और वित्तीय दायरे को दर्शाता है।

आपराधिक इतिहास और पुलिस टीम

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी अनिल कुमार के खिलाफ वर्ष 2015 में भी हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है, जबकि जितेंद्र के खिलाफ वर्ष 2014 में जयपुर में मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। इंतजार अली का फिलहाल कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।

राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा रोडमैप तैयार

जयपुर । राजस्थान की उपमुख्यमंत्री मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में बुधवार को पर्यटन भवन, जयपुर में पर्यटन विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में पर्यटन स्थलों, विरासत संरचनाओं और सांस्कृतिक धरोहरों के विकास के साथ-साथ अधोसंरचना और डिजिटल तकनीकों को सुदृढ़ बनाने से जुड़े बिंदुओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

पर्यटन सचिव रवि जैन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्थान में पर्यटन विकास ऐसा हो, जिससे राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचे।

बैठक में झुंझुनूं में 'वार म्यूजियम' स्थापित करने की घोषणा की गई।इस संग्रहालय में राजस्थान के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाएं, ऐतिहासिक युद्धों से जुड़ी सामग्री और युद्ध कौशल को डिजिटल और भौतिक स्वरूप में प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (छ्क्क्र) शीघ्र तैयार कर बजट आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

अल्बर्ट हॉल संग्रहालय को मिलेगा स्मार्ट म्यूजियम का स्वरूप

जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल संग्रहालय को आधुनिक तकनीक के साथ 'स्मार्ट म्यूजियम' के रूप में विकसित किया जाएगा।

इसके तहत डिजिटल लाइट एंड साउंड शो, इंटरैक्टिव डिस्प्ले, वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) जैसे नवाचार शामिल किए जाएंगे। यह पहल संग्रहालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख संग्रहालयों और किलों के डिजिटलीकरण की योजना को 25 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी गई है।

वर्चुअल टूर सिस्टम जैसी तकनीकों को शामिल किया गया है।पहले चरण में आगामी छह माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

पुष्कर के लिए 100 करोड़ रुपये की विकास योजना

बैठक में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुष्कर के लिए 100 करोड़ रुपये की विकास योजना की प्रस्तुति दी गई।

प्रस्तावित परियोजनाओं में शामिल हैं

ब्रह्मा मंदिर कोरिडोर
घाटों का जीर्णोद्धार
थीम पार्क में लेज़र शो
डिजिटल गाइडिंग सिस्टम
सावित्री वाटिका का विकास
ब्रह्मा से वराहा चौक तक कॉरिडोर निर्माण

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेला ग्राउंड का समुचित विकास भी योजना में सम्मिलित किया जाए।अजमेर विकास प्राधिकरण को डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को भव्य रूप से विकसित करने तथा संग्रहालयों में नवाचार पर भी चर्चा की गई।वहीं ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में आदिवासी जीवनशैली को शोकेस करने वाले शिल्पग्राम और जनजातीय संग्रहालय विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। छ्क्क्रतैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

जल संरक्षण और विरासत संरक्षण पर विशेष बल

बैठक में राजस्थान की पारंपरिक बावड़ियों और जल संरचनाओं के संरक्षण पर भी चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ कंसल्टेंट्स की राय लेकर संरक्षण कार्य किए जाएं ताकि जल संरक्षण की परंपरा और लोक संस्कृति का दीर्घकालिक संरक्षण संभव हो सके।

साथ ही जमवाय माता मंदिर, खाटू श्याम जी, और मालासेरी डूंगरी जैसे धार्मिक स्थलों के विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रियाओं की अद्यतन स्थिति भी साझा की गई।

उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य की एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी को जून माह के भीतर अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही राजस्थान पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करने के लिए रोड शो आयोजित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा गया है।

महापौर सौम्या गुर्जर ने वार्ड नं. 118 में विभिन्न विकास कार्यों का किया शिलान्यास

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में स्थित जगतपुरा जोन के वार्ड नंबर 118 में बुधवार को विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ एवं लोकार्पण किया गया। सेक्टर 19 में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास बुधवार को विधायक कैलाश वर्मा एवं नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर के कर-कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद ममता शर्मा, जनप्रतिनिधि सहित आम जन मौजूद रहे। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर जनहित के कार्यों के लिए हमेशा अग्रसर रहा है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लक्ष्य के साथ हम सभी कार्य कर रहे हैं। जो वादे हमने चुनाव के समय किए थे उन सभी को हम पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं उन कार्यों में से लगभग कार्य पूरे कर लिए गए हैं, शेष कार्य भी प्रगतिरत हैं।

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
लोकार्पण
डॉ. सौम्या गुर्जर

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास कार्यों को गति मिल रही है। इसके अतिरिक्त जगतपुरा जोन के वार्ड 120 व 121 में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया।

उद्योग विभाग ने 'राइजिंग राजस्थान-पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025' की तैयारियों की समीक्षा की

जयपुर, ।'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024' की उल्लेखनीय सफलता के बाद, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार अब आगामी 'राइजिंग राजस्थान- पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025' की तैयारियों में जुट गया है। यह कॉन्क्लेव 11 और 12 दिसंबर 2025 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। उद्योग भवन में आयोजित बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा की अध्यक्षता में सम्मेलन की रूपरेखा और कार्यक्रम की व्यापक तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक में दो दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान प्रस्तावित सत्रों, राउंड टेबल पर चर्चाओं और बिजनेस एक्सपो जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही, 10 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई।

प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा ने कहा, 'राइजिंग राजस्थान- पार्टनरशिप कॉन्क्लेव' का मुख्य फोकस निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने, उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को प्रदर्शित करने और राज्य में उद्योग अनुकूल परिवेश को रेखांकित करने पर होगा। यह सम्मेलन सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सशक्त बनाने का एक प्रभावशाली मंच बनेगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह आयोजन राज्य में किए गए निवेशों के ठोस कार्यान्वयन और विभिन्न सरकारी विभागों की आर्थिक विकास में भूमिका को सामने लाने का कार्य करेगा। साथ ही, उद्योग विभाग द्वारा बुनियादी ढांचा, आईटी, खनन, डीप-टेक, कौशल,बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा), जीसीसी (वैश्विक क्षमता केंद्र), स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे विविध क्षेत्रों में निवेश योग्य परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रस्तुत की जाएगी। इन परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के साथ सह-निर्माण और साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

इस बैठक में उद्योग और वाणिज्य आयुक्त रोहित गुप्ता, निवेश संवर्धन ब्यूरो (ङ्क्ष्क्र), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लिमिटेड (ङ्क्ष्ठ्ठ्ह) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित 'राइजिंग राजस्थान' समिट में राज्य सरकार ने रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षरित किए थे। मार्च 2025 में आयोजित इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई थी कि इनमें से 3.08 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पहले ही जमीन पर उतर चुके हैं।

'राइजिंग राजस्थान- पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025' न केवल इन परियोजनाओं के प्रगति और प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, बल्कि यह निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को और सशक्त कर, राजस्थान को व्यापार एवं निवेश के लिए एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा।

बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया की जटिल पर्यावरण समस्या

(लेखक- ललित गर्ग)

बढ़ते तापमान, बदलते जलवायु एवं ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल कर समुद्र का जलस्तर तीव्रगति से बढ़ा रहे हैं। जिससे समुद्र किनारे बसे अनेक नगरों एवं महानगरों के डूबने का खतरा मंडराने लगा है। इंसानों को प्रकृति, पृथ्वी एवं पर्यावरण के प्रति सचेत करने के लिये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो पर्यावरण, प्रकृति एवं पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोज्य यह दिवस दुनिया भर के लाखों लोगों को हमारे ग्रह की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के साझा मिशन के साथ एकजुट करता है। बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया की एक गंभीर एवं जटिल समस्या है, इसीलिये 2025 में इस दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित है। कोरिया गणराज्य वैश्विक समारोह की मेज़बानी करेगा। दशकों से प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया के हर कोने में फैल चुका है, यह हमारे पीने के पानी, हमारे खाने, हमारे शरीर, हमारे पर्यावरण में समा रहा है। इस प्लास्टिक कचरे की गंभीर समस्या से निपटने का एक वैश्विक संकल्प निश्चित ही एक समाधान की दिशा बनेगा। हर साल 430 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से लगभग दो-तिहाई केवल एक बार उपयोग के लिए होता है और जल्दी ही फेंक दिया जाता है।

1973 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के नेतृत्व में पर्यावरण जागरूकता के लिए यह दिवस सबसे बड़ा वैश्विक अभियान बन गया है, जो आज की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए 150 से अधिक देशों के विशाल वैश्विक दर्शकों को शामिल करता है। गत वर्ष इस दिवस की मेजबानी करते हुए सऊदी अरब ने भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए सकारात्मक प्रयासों का जश्न मनाया और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले निजी और परोपकारी संगठनों के लिए अधिक समर्थन और वित्त पोषण की घोषणा की। यह सर्वविदित है कि इंसान व प्रकृति के बीच गहरा संबंध है। इंसान के लोभ, सुविधावाद एवं तथाकथित विकास की अवधारणा ने पर्यावरण का भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण न केवल नदियां, वन, रेगिस्तान, जलस्रोत सिकुड़ रहे हैं बल्कि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, तापमान का 50 डिग्री पार करना जो विनाश का संकेत तो है ही, जिनसे मानव जीवन भी असुरक्षित होता जा रहा है। इन वर्षों में बढ़ी हुई गर्मी एवं तापमान ने न केवल जीवन को जटिल बनाया बल्कि अनेक लोगों की जान भी गयी। पूरी दुनिया में बढ़ता प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु अराजकता और जैव विविधता विनाश का एक जहरीला मिश्रण स्वस्थ भूमि को रेगिस्तान में बदल रहा है, संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र को मृत क्षेत्रों में बदल रहा है और मानव जीवन पर तरह-तरह के खतरे पैदा कर रहा है।

प्रकृति को पस्त करने, वायु एवं जल प्रदूषण, कृषि फसलों पर घातक प्रभाव, मानव जीवन एवं जीव-जन्तुओं के लिये जानलेवा साबित होने के कारण समूची दुनिया में बढ़ते प्लास्टिक एवं माइक्रोप्लास्टिक के कण एक बड़ी चुनौती एवं संकट है। पिछले दिनों एक अध्ययन में मनुष्य के मस्तिष्क में प्लास्टिक के नैनो कणों के पहुंचने पर चिंता जतायी गई थी। दावा था कि प्रतिदिन सैकड़ों माइक्रोप्लास्टिक कण सांसों के जरिये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे तमाम नये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय शोध-सर्वेक्षण-अध्ययन चेतावनी दे रहे हैं कि हमारी सांसों, प्रकृति, पर्यावरण, पेयजल व फसलों में घातक माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी एक गंभीर संकट है। संकट तो यहां तक बढ़ गया है कि प्लास्टिक के कण पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने लगे हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला में शामिल कई खाद्यान्नों की उत्पादकता में गिरावट आ रही है। ऐसा निष्कर्ष अमेरिका-जर्मनी समेत कई देशों के साझे अध्ययन के बाद सामने आया है। दरअसल, प्लास्टिक कणों के हस्तक्षेप के चलते पौधों के भोजन सृजन की प्रक्रिया बाधित हो रही है। इस तरह माइक्रोप्लास्टिक की दखल भोजन, हवा व पानी में होना न केवल प्रकृति, कृषि, पर्यावरण वरन मानव अस्तित्व के लिये गंभीर खतरे की घंटी ही है। जिसे बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सरकारों को इस संकट से मुक्ति की दिशाएं उद्घाटित करने के लिये योजनाएं बनानी चाहिए, इसके लिये इस वर्ष की थीम से व्यापक बदलाव की संभावनाएं हैं।

माइक्रोप्लास्टिक हमारे वातावरण का एक हिस्सा बन चुके हैं। प्लास्टिक की बहुलता एवं निर्भरता के कारण मौत हमारे सामने मंडरा रही है। हम चाहकर भी प्लास्टिकमुक्त जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों को देखते हुए विभिन्न देशों की सरकारों ने ठान लिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए कोई जगह नहीं होगी। भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व में ही देश को स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने की अपील करते हुए एक महाभियान का शुभारंभ कर चुके हैं। प्लास्टिक के कारण देश ही नहीं, दुनिया में विभिन्न तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके सीधे खतरे दो तरह के हैं। एक तो प्लास्टिक में ऐसे बहुत से रसायन होते हैं, जो कैंसर का कारण माने जाते हैं। इसके अलावा शरीर में ऐसी चीज जा रही है, जिसे हजम करने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है, यह भी कई तरह से सेहत की जटिलताएं पैदा कर रहा है। इसलिए आम लोगों को ही इससे मुक्ति का अभियान छेड़ना होगा, जागृति लानी होगी।

शोधकर्ताओं ने केरल में दस प्रमुख ब्रांडों के बोतलबंद पानी को अध्ययन का विषय बनाया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्लास्टिक की बोतल के पानी का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रतिवर्ष 153 हजार प्लास्टिक कण प्रवेश कर जाते हैं। पिछली सदी में जब प्लास्टिक के विभिन्न रूपों का अविष्कार हुआ, तो उसे विज्ञान और मानव सभ्यता की बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया था, अब जब हम न तो इसका विकल्प तलाश पा रहे हैं और न इसका उपयोग ही रोक पा रहे हैं, तो क्यों न इसे विज्ञान और मानव सभ्यता की सबसे बड़ी असफलता एवं त्रासदी मान लिया जाए? अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने यहां बारिश के पानी के नमूने जमा किए। ये नमूने सीधे आसमान से गिरे पानी के थे, बारिश की वजह से सड़कों या खेतों में बह रहे पानी के नहीं। जब इस पानी का विश्लेषण हुआ, तो पता चला कि लगभग 90 फीसदी नमूनों में प्लास्टिक के बारीक कण या रेशे थे, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते। लगातार पांव पसार रही माइक्रोप्लास्टिक की तबाही इंसानी गफलत को उजागर तो करती रही है, लेकिन समाधान का कोई रास्ता प्रस्तुत नहीं कर पाई। ऐसे में अगर विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक के संकट का दूर करने की कुछ ठानी है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण की उससे भी ज्यादा खतरनाक एवं जानलेवा स्थिति है, यह एक ऐसी समस्या बनकर उभर रही है, जिससे निपटना अब भी दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुछ समय पहले एक खबर ऐसी भी आई थी कि एक चिड़ियाघर के दरियाई घोड़े का निधन हुआ, तो उसका पोस्टमार्टम करना पड़ा, जिसमें उसके पेट से भारी मात्रा में प्लास्टिक की थैलियां मिलीं, जो शायद उसने भोजन के साथ ही निगल ली थीं। कनाडाई वैज्ञानिकों द्वारा माइक्रोप्लास्टिक कणों पर किए गए विश्लेषण में चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। विश्लेषण में पता चला है कि एक वयस्क पुरुष प्रतिवर्ष लगभग 52000 माइक्रोप्लास्टिक कण केवल पानी और भोजन के साथ निगल रहा है। इसमें अगर वायु प्रदूषण को भी मिला दें तो हर साल करीब 1,21,000 माइक्रोप्लास्टिक कण खाने-पानी और सांस के जरिए एक वयस्क पुरुष के शरीर में जा रहे हैं। अमेजन एवं फिलीपकार्ट जैसे आनलाइन व्यवसायी प्रतिदिन 7 हजार किलो प्लास्टिक पैकेजिंग बैग का उपयोग केवल भारत में करते हैं। इन कम्पनियों को भी प्लास्टिकमुक्त दुनिया के घेरे में लेने के लिये कठोर कदम उठाने चाहिए। संकट का एक पहलू यह भी है कि लोग सुविधा को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन प्लास्टिक के दूरगामी घातक प्रभावों को लेकर आंख मूंद लेते हैं।

> 1973 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के नेतृत्व में पर्यावरण जागरूकता के लिए यह दिवस सबसे बड़ा वैश्विक अभियान बन गया है, जो आज की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए 150 से अधिक देशों के विशाल वैश्विक दर्शकों को शामिल करता है। गत वर्ष इस दिवस की मेजबानी करते हुए सऊदी अरब ने भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए सकारात्मक प्रयासों का जश्न मनाया और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले निजी और परोपकारी संगठनों के लिए अधिक समर्थन और वित्त पोषण की घोषणा की।

संपादकीय

जीवन बदले साक्षरता

निस्संदेह, भारत की साक्षरता का प्रतिशत करीब 81 फीसदी होना एक सराहनीय उपलब्धि व मील का पत्थर ही है। देश की आजादी के वक्त की साक्षरता स्थिति से इसकी तुलना करें तो इसे उपलब्धि की तौर पर देखा जाना चाहिए। किसी समाज में साक्षरता का स्तर उसकी प्रगति का आईना ही होता है। ये आंकड़े हमारे समाज की शिक्षा तक पहुंच में निरंतरता का पर्याय भी हैं। हालांकि, 2023-24 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीएलएफएस के आंकड़ों से यह भी उजागर होता है कि सार्वभौमिक साक्षरता की ओर राष्ट्र का यह कदम निरंतर कई असमानताओं से भी बाधित है। खासतौर पर यह भेद लिंग और क्षेत्रीय आधार पर नजर आता है। उदाहरण के लिए देखें तो शहरी क्षेत्रों में साक्षरता की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। जिसका मुख्य कारण शहर केंद्रित विकास को तरजीह व शिक्षा के लिये अनुकूल परिस्थितियों का होना भी है। आंकड़े बताते हैं कि शहरी भारत में साक्षरता की दर 88.9 है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में यह 77.5 फीसदी ही हो पायी है। निश्चित रूप से विभिन्न राज्यों में प्रतिध्वनित यह शहरी व ग्रामीण साक्षरता का अंतर शिक्षा के बुनियादी ढांचे, योग्य शिक्षकों की उपलब्धता और सीखने के अवसरों में असमानता को ही दर्शाता है। कमोबेश इसी प्रकार देश के विभिन्न राज्यों में लैंगिक असमानताएं भी नजर आती हैं। यह विडंबना की कही जाएगी कि कई राज्यों में लड़कियों की शिक्षा पर दशकों से नीतिगत स्तर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता के मुकाबले कहीं आगे नजर आती है। निश्चित रूप से इसके मूल में सामाजिक रूढ़ियां, सामाजिक चेतना का अभाव व आर्थिक विकास की विसंगतियां निहित हैं। जिसके चलते लड़कियों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के बीच स्कूलों की दूरी और आवागमन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न हो पाना भी महिला शिक्षा के प्रतिशत में गिरावट का कारक बनती है। इन तमाम कारणों को नये सिरे से संबोधित करने की जरूरत है। लेकिन वहीं कुछ राज्यों में लक्ष्यों पर केंद्रित अभियानों व शासन-प्रशासन की सक्रियता के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। लक्षद्वीप, दिल्ली, तमिलनाडु और त्रिपुरा के परिणाम दर्शाते हैं कि जब शासन की सक्रियता, लोगों की पहुंच और सामुदायिक जुड़ाव एक साथ आते हैं तो कुछ भी संभव है। दरअसल, आर्थिक विसंगतियों से जूझते व सामाजिक व आर्थिक सुधारों को अमल में न ला सकने वाले राज्य साक्षरता के लक्ष्य राष्ट्रीय अनुपात में नहीं प्राप्त कर सके। सबसे कम साक्षरता दर वाले बिहार की स्थिति गरीबी,अपर्याप्त स्कूली शिक्षा, सांस्कृतिक कारकों व शिक्षा की राह में बाधा डालने वाली सामाजिक बाधाओं के जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करती है। यहां इन उत्साहजनक आंकड़ों के बावजूद कई सवाल हमारे सामने पैदा होते हैं। प्रश्न यह भी है कि हम किस तरह की साक्षरता विकसित कर रहे हैं? क्या शिक्षा की गुणवत्ता इस स्तर की है कि वो लोगों के जीवन में व्यापक बदलावों का कारक बन सके? बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है पड़ताल इस बात की भी की जानी चाहिए कि साक्षरता क्या वास्तव में प्रगतिशील सोच, नागरिक दायित्वों और आर्थिक जीवन में सार्थक रूप से भाग लेने की क्षमता विकसित करती है?

मां गंगा के अवतरण की याद दिलाता है गंगा दशहरा

(लेखक- डॉ श्रीगोपाल नारसन)

भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जिस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण किया,उस पवित्र दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे।जिसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की थी। गंगा दशहरा पर हर वर्ष गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाती हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप मिट जाते हैं।गंगा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में धरती पर अवतरित हुई थी। इस साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 4 जून की रात 11 बजकर 54 मिनट पर शुरू हो रही है।ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 5 जून, गुरुवार को गंगा दशहरा मनाया जा रहा है।गंगा दशहरा पर सुबह 9 बजकर 14 मिनट पर सिद्धि योग है।इसके साथ ही इस दिन रवि योग और हस्त नक्षत्र भी है,जो दोपहर 1 बजकर 2 मिनट पर तैतिल करण रहेगा। गर करण योग दोपहर 2 बजकर 15 मिनट तक रहने वाला है।

गंगा में डुबकी लगाते समय 'ऊँ नमः शिवायै नारायण्यै दशहरायै गंगायै नमः' मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता हैं। गंगा दशहरा के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान-धर्म के कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दशहरा का अर्थ 10 मनोविकारों के विनाश से है। ये दस मनोविकार हैं-क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी।जिनसे मुक्ति के लिए ज्ञान गंगा का स्नान करने से हम विकारमुक्त होकर पवित्र बन सकते है। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या, उनके अथक प्रयास और परिश्रम से इसी दिन गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर शिव की जटाओं में विराजमान हुई थी और शिवजी ने अपनी शिखा को खोल कर गंगा को धरती पर जाने की अनुमति दी थी। इसलिए गंगा के धरा अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है।

गंगा दशहरा के दिन प्रातः काल गंगा में स्नान करके मां गंगा की आरती करने से समस्त पापों का विनाश हो जाने की धार्मिक मान्यता है। गंगा का जल हमेशा पवित्र व गुणकारी होता है,उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते और इसका जल प्रदूषित नहीं होता । इसलिए इस जल में स्नान करने से रोगों का विनाश हो जाता है।

गंगा दशहरा के दिन स्नान, ध्यान और तर्पण करने से शरीर शुद्ध और मानसिक विकारों से मुक्त हो जाता है।अमृत दायिनी मां गंगा के स्पर्श मात्र से ही चराचर जीवो के पापों का अंत हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। कहते है कि एक बार महाराज सगर ने एक बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणाम स्वरूप अंशुमान ने सगर की साठ हजार प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला।फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर-चोर चिल्लाने लगी।

महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तपस्या की थी।भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने गंगा की मांग की।इस पर ब्रह्मा ने कहा- राजन! तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो? परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए।

महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध लीं। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका।अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। तब कहीं जाकर भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूट कर गंगाजी हिमालय की घाटियों में कल-कल निनाद करके मैदान की ओर आई।इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों-युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणीमात्र को जीवनदान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है और गंगा के अवतरण की याद में गंगा दशहरा मनाया जाता है।

(चिंतन-मनन)

सच्चा पुरुषार्थ

यह बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद की चर्चा दुनिया भर में फैल चुकी थी। उनके विचारों को लेकर हर जगह विचार-विमर्श चल रहा था। उन्हें एक आदर्श के रूप में स्थापित होता देख एक विदेशी महिला बहुत प्रभावित हुई। उसने स्वामी विवेकानंद से विवाह करने का मन बना लिया। बस, इसके बाद वह हरदम उन्हीं के बारे में सोचती रहती। संयोग से एक दिन स्वामी विवेकानंद एक सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे तो उसने उनसे मिलने की ठान ली। वह किसी तरह उसी स्थान पर जा पहुंची जहां सम्मेलन हो रहा था।

महिला स्वामी जी के समीप जाकर निर्भीकता से बोली,स्वामी जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद ने उससे पूछा,क्यों, विवाह तुम आखिर मुझसे ही क्यों करना चाहती हो? क्या तुम यह नहीं जानती कि मैं तो एक संन्यासी हूं? महिला ने पूरी विनम्रता से कहा,देखिए, बात ये है कि मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजमय पुत्र चाहती हूं। और वह तो तभी संभव होगा जब आप मुझसे विवाह करेंगे।

यह सुनकर स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, देखो, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु एक उपाय अवश्य है। महिला बोली,कैसा उपाय? स्वामी विवेकानंद बोले,आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं और आप मेरी मां बन जाएं। आपको मेरे जैसा पुत्र मिल जाएगा। विवेकानंद की यह बात सुनकर विदेशी महिला उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली,स्वामी जी, सचमुच आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं। इसे कहते हैं पुरुष और ये होता है पुरुषार्थ। सच्चा पुरुषार्थ तभी होता है जब पुरुष नारी के प्रति अपने मन में पुत्र जैसा भाव ला सके और उसमें मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके।

विचार मंथन

कोरोना महामारी के मोर्चे पर सरकार की तैयारियां?

(लेखक- सनत जैन)

भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज़ हो गई है। केवल 13 दिनों में संक्रमण के मामले 257 से बढ़कर 4026 तक पहुंच गए हैं। इसमे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, सरकार की ओर से इस बार कोई ठोस गाइडलाइन या रणनीति सामने नहीं आई है। अस्पतालों में कोविड वार्ड नदारद हैं। ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत फिर हो सकती है। पहले से ही जर्जर स्वास्थ्य ढांचा चरमराने की कगार पर है। पीएम केयर फंड के माध्यम से जो अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगवाए गए थे, वे बंद पड़े हुए हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोरोना के वायरस और इलाज को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसके कारण आम लोगों में डर और भय का वातावरण देखने को मिल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के विनाशकारी अनुभव के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें इस बार पूरी तरह बेपरवाह नज़र आ रही हैं। न तो अस्पतालों में कोविड बेड आरक्षित किये गये हैं, ना ही कोरोना वायरस की टेस्टिंग को लेकर कोई दिशा निर्देश अथवा सख्ती शुरू की गई है। कई जिलों में आरटी-पीसीआर जांच सीमित हैं। ऐसे में असल संक्रमण की स्थिति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। सबसे गंभीर चिंता यह है, इस बार कोविड के नए वैरिएंट्स—जैसे जेएन-1, एक्सबीबी1.16 और बीए.2.86—तेजी से फैल रहे हैं। इन पर पहले की वैक्सीन कारगर नहीं है। इसका दावा खुद स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इलाज का कोई निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार इस पर कोई संज्ञान लेते नहीं दिख रही है। सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी है, कि वहां सामान्य मरीजों को भी ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है। यदि संक्रमण और फैला तो सरकारी एवं निजी अस्पतालों मे कोरोना बीमारी के इलाज के नाम पर मनमानी एक बार फिर आम जनता की जेब पर भारी पड़ेगी। इससे निपटने के लिए कोई स्पष्ट नीति या तैयारी को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी लोगों को आश्चर्य में डाल रही है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में महामारी से निपटने के लिए पूर्व योजना, संसाधनों का भंडारण, पारदर्शी रिपोर्टिंग एवं केंद्र-राज्यों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक हैं। दुर्भाग्यवश, यह सब समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ही सीमित है। अगर अब भी सरकार नहीं जागी, तो देश एक बार फिर उसी अराजकता और भय के दौर में लौट सकता है, जो दूसरी लहर के समय देखा गया था। कोविड-19 में दूसरी और तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं। सरकार ने 4.60 लाख मौत होना स्वीकार की थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा 30.7 लाख मौत भारत में होने की पुष्टि की थी। बीबीसी, टेलीग्राफ और कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना महामारी में बीमारियों के जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे उसमें भारत में कम से कम 30.7 मौतें होना बताया गया था। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अनुसार भारत की जनसंख्या के हिसाब से कोरोना में मरने वालों की संख्या 0.3 फीसदी थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे 0.6 माना गया था। 2021 में इस महामारी के कारण जो विनाश हुआ था, उसको देखते हुए भारत से दुनिया के देशों को कोरोना के नए वायरस को लेकर काफी सजग होने की जरूरत है। वह भी तब जब इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अभी तक विश्व स्तर पर इसके इलाज के बारे में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। ऐसे में चिंता और भी बढ़ जाती है।

सरकार को तुरंत कोरोना बीमारी के उपचार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। नए वैरिएंट्स पर वैज्ञानिक समीक्षा, उपचार, कोविड मरीज के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित करना, मुफ्त जांच, दवाओं की उपलब्धता और जनजागरूकता अभियान चलाना जल्दी से जल्दी शुरू करना होगा। यह समय आश्वासनों का नहीं, त्वरित कार्रवाई का है। महामारी को लेकर की गई लापरवाही की कीमत देश पहले ही भोग चुका है। केंद्र एवं राज्य सरकारों को कोरोना के इस नए वायरस को गंभीरता से लेना होगा। इसका इलाज किस तरह से हो जिसका लाभ मरीजों को मिले तथा कोरोना की बीमारी के जो विभिन्न किस्म के वायरस बार-बार नए-नए रूपों में जन्म ले रहे हैं। उसके लिए टीका विकसित करने जैसी स्थितियों पर विचार करना होगा। आशा की जाती है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें त्वरित कार्यवाही करें। देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस से निपटने के लिए नई गाइडलाइन जारी करें। वायरस से किस तरीके से निपटा जा सकता है। इसका उपचार कैसे होगा इसकी जानकारी निचले स्तर तक भेजने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है।

नवनियुक्त अधिकारियों को राष्ट्रपति ने दी नसीहत कहा- सहानुभूति और निष्पक्षता बनाए रखें

नई दिल्ली।

नवनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नसीहत देते हुए कहा है कि लोक सेवा की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले मूल्यों पर कायम रहते हुए अपने प्राधिकार का इस्तेमाल सहानुभूति और निष्पक्षता के साथ करें। मुर्मू ने कहा कि समावेशी विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों के प्रयासों में विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि हाशिये पर पड़े और कमजोर वर्ग देश को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा में पीछे न छूट जाएं।

राष्ट्रपति ने कहा, जब गरीब और वंचित लोग विकास और समृद्धि का अनुभव करेंगे, तभी हम विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब होंगे। मुर्मू यहां राष्ट्रपति भवन में राज्य सिविल सेवाओं से नियुक्त आईएएस अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं, जो मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 127वें प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये अधिकारी यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने आये थे।

उन्होंने कहा कि नौकरी करते समय उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी और नवाचार बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

मुर्मू ने कहा, डिजिटल उपकरण सेवा मुहैया कराने की स्थिति में सुधार से लेकर डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम बनाने तक,कुशल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल शासन प्रणाली बनाने में मदद कर सकते हैं। यह जरूरी है कि आप एआई, ई-गवर्नेंस और डिजिटल फीडबैक तंत्र में नवाचारों को अपनाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंचें। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा को परिभाषित करने वाले मूलभूत मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं आपसे अपने आचरण में ईमानदारी बनाए रखने, अपने कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही बनाए रखने का आग्रह करती हूं। आपको सहानुभूति और निष्पक्षता के साथ

अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उदाहरण पेश करेंगे और उन मूल्यों में निहित रहेंगे जो सार्वजनिक सेवा की भावना को दर्शाते हैं।

संक्षिप्त समाचार

लालू यादव के कार्यकाल में रेल मंत्रालय ने आवेदनों की मंजूरी के लिए दबाव डाला

सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में किया दावा

नई दिल्ली।

सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में दावा किया कि रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में मंत्रालय ने ग्रुप-डी के उम्मीदवारों के नौकरी के आवेदनों को मंजूरी देने के लिए दबाव डाला था, जिन्होंने कथित तौर पर राजद प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए या हस्तांतरित किए थे। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कथित भूमि के लिए नौकरी घोटाले में आरोपों पर दलीलें सुन रहे थे। इसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर के पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र में 2004 से 2009 के बीच नियुक्तियां की गई थीं। इस दौरान लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। कार्यवाही के दौरान विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने रेखांकित किया कि पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदक बिहार से थे और ये ज्यादातर गरीब लोग थे, जिनके लिए सरकारी नौकरी हासिल करना फायदेमंद होता।

इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में मरीज की मौत, 70 को डायरिया की शिकायत

हैदराबाद।

तेलंगाना सरकार के अधीनस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ (आईएमएच) में एक मरीज की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि लगभग 70 मरीजों ने अचानक उल्टी और दस्त की शिकायत की, जिससे संस्थान में हड़कंप मच गया।

हैदराबाद के जिलाधिकारी अनुदीप दुरीशेट्टी ने स्वयं आईएमएच का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मृतक मरीज सुबह से कोई गतिविधि नहीं कर रहा था। उसे होश में लाने के लिए सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) भी दिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बाद में मरीज को सरकारी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल, मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है और जांच जारी है।

70 मरीजों को डायरिया जैसे लक्षण

जिलाधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम तक लगभग 65 से 70 मरीजों में उल्टी और दस्त जैसे लक्षण पाए गए। डॉक्टरों की टीम ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और आवश्यक इलाज भी शुरू कर दिया गया है। संस्थान में खाद्य व पेयजल की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। प्रारंभिक आशंका है कि किसी प्रकार का खाद्य या जलजनित संक्रमण इस घटना का कारण हो सकता है।

सुहास शेट्टी हत्याकांडः एक और गिरफ्तारी, अब तक 16 आरोपी पकड़े गए

मुख्य आरोपी को पनाह देने के आरोप में अब्दुल रजाक गिरफ्तार

मंगलुरु।

सुहास शेट्टी हत्याकांड मामले में मंगलुरु पुलिस की जांच लगातार तेज़ होती जा रही है। ताज़ा कार्रवाई में सिटी क्राइम ब्रांच ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता को शरण देने का आरोप लगा है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान 59 वर्षीय अब्दुल रजाक के रूप में हुई है, जो मंगलुरु का ही निवासी है। पुलिस के मुताबिक, रजाक ने हमले के बाद मुख्य आरोपी को छिपने में मदद की थी। इस गिरफ्तारी के साथ ही इस हाई-प्रोफाइल हत्या मामले में अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यहां बताते चलें कि बीते महीने कुख्यात बदमाश और हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की शहर में एक समूह ने निर्मम हत्या कर दी थी। यह मामला राज्यभर में चर्चा का विषय बन गया था, जिसे सांप्रदायिक दृष्टि से भी संवेदनशील बताया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीसीबी ने जांच की कमान संभाली थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब्दुल रजाक से पूछताछ जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां भी संभव हैं। मामले से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है।

नीता अंबानी के पास है 200 करोड़ का बाजूबंद, शाहजहां परिवार से है संबंध

सालों से अंबानी परिवार महंगी और एंटिक चीजों का है शौकीन

नई दिल्ली।

अंबानी परिवार देश के सबसे अमीर परिवारों में शामिल हैं। इनके गहने से लेकर कपड़ों तक की चर्चा आए दिन होती रहती है। सालों से अंबानी परिवार कई महंगी वस्तु खरीद रहा है और इनका कलेक्शन और बढ़ा है। ये वस्तु अनोखी और महंगी हैं। नीता अंबानी के पास बहुत ही खास बाजूबंद है, जिसे उन्होंने मिस वल्र्ड फाइनल 2024 में पहना था। इस बाजूबंद का मुगल शासन के शाहजहाँ परिवार से संबंध है। यहीं कारण है कि इसकी बनावट में शाही कारीगरी झलकती है। इसकी कीमत 200 करोड़ रुपए हैं। इस प्राचीन बाजूबंद को प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसमें कई तरह के खास हीरे जड़े हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री-वेडिंग में नीता अंबानी ने हीरो का हार पहना था। ये उस समय अपनी खूबसूरती के चलते चर्चा में था। इस हार की कीमत 400 से 500 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। अंबानी परिवार की बेटी ईशा अंबानी अपने फैशन के लिए हमेशा चर्चा में बनी रहती है। इनके पास एक शानदार हीरों का हार है। इस नेकलेस की कीमत 167 करोड़ हैं। इस नेकलेस का साधारण होना ही सभी को आकर्षक करता है। अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट के पास कई महंगी चीजें हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इनकी पत्नी के पास हीरो और मोतियों से बना शानदार चोकर है। ये चोकर उन्हें नीता अंबानी की तरफ से दिया गया था। हालांकि इस चोकर की क्या कीमत है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अनंत अंबानी के पास एक पार्टक फिलिप की वॉच है। जिसका फेस डाइल दोनों तरफ है। इसका जटिल डिजाइन है और इसकी कीमत 54 करोड़ रुपए हैं। जटिल डिजाइन के मामले में ये वॉच सबसे आगे हैं। वही अनंत अंबानी को सगाई के दौरान उनके भाई आकाश अंबानी ने कार्टियर ब्रोच गिफ्ट किया था। ये ब्रोच 18 कैरेट से बनाया गया था, जिसमें हीरो और अन्य महंगे सामान का इस्तेमाल भी हुआ है। इसकी कीमत 13.2 करोड़ बताई जाती है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक आज, लिए जा सकते हैं कई बड़े फैसले

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज 4 जून को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक शाम 5 बजे सुषमा स्वराज भवन में होगी। खास बात यह है कि यह बैठक हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी सभी मंत्रियों को इस सैन्य ऑपरेशन की जानकारी देंगे, साथ ही कुछ अहम नीतिगत फैसले भी लिए जा सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, बैठक के दौरान मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल (मोदी 3.0) का एक साल पूरा कर रही है, ऐसे में यह बैठक राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई मंत्रालय अपने कार्यों का प्रजेंटेशन प्रधानमंत्री के समक्ष देंगे। इनमें जल शक्ति मंत्रालय प्रमुख रूप से शामिल है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में बीते वर्षों की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाएं।

बुकलेट में संजोई जाएंगी उपलब्धियां

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सभी मंत्रालयों से उनके कार्यों की रिपोर्ट मिली है, जिन्हें समेकित कर एक विशेष बुकलेट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा,

मंत्रालयों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनसंपर्क बढ़ाने और सरकार की उपलब्धियों को सामने लाने के निर्देश दिए गए हैं।

कमल हासन ने टिप्पणी पर माफी मांगने से किया इनकार, कोर्ट ने लगाई फटकार

हाईकोर्ट फिल्म ठग लाइफ के रिलीज पर सुरक्षा देने की याचिका पर करा रहा सुनवाई

बैंगलुरु।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभिनेता कमल हासन को उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर माफी मांगने से इनकार करने पर फटकार लगाई। कोर्ट कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ के राज्य में रिलीज होने पर सुरक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। फिल्म के निर्माताओं ने कोर्ट को बताया कि यह फिल्म 5 जून को कर्नाटक में रिलीज नहीं होगी, जो पूरे देश में रिलीज की तय तिथि है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 10 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने अभिनेता हासन की टिप्पणी के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन और कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा बहिष्कार के आह्वान के मद्देनजर राज्य में फिल्म की रिलीज के लिए पर्याप्त सुरक्षा देने का अनुरोध किया था। केएफसीसी ने कमल हासन से माफी मांगने की मांग की है। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा कि अभिनेता एक बार माफी मांगने से स्थिति सुलझ सकती थी, उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किसी की विशेष रूप से जनसमूह की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की सीमा तक नहीं किया जा सकता।

न्यायाधीश ने कहा कि अभिनेता के हालिया बयान से कर्नाटक के लोगों की भावना को ठेस पहुंची है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की भावनात्मक और सांस्कृतिक पहचान होती है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी

व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है जो पूरे भाषाई समुदाय के गौरव को ठेस पहुंचाए। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने सवाल किया कि क्या आप कमल हासन इतिहासकार या भाषाविद् हैं जो ऐसा बयान दे रहे हैं? एक माफी से स्थिति सुलझ सकती थी।

रोजमर्रा के जीवन में एआई की भूमिका को लेकर भारतीय सबसे ज्यादा खुश

नई दिल्ली।

रोजमर्रा के जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बढ़ती भूमिका को लेकर दुनिया में भारतीय सबसे ज्यादा खुश हैं। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि एक सर्वे से पता चला है कि भारत में 30 फीसदी लोग एआई के विकास को लेकर खुश हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के 27 फीसदी पार्टिसिपेंट्स एआई को लेकर आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। वहीं सर्वे में 55 फीसदी भारतीयों ने एआई के साथ उच्च इंगेजमेंट की संभावना जताई, उसके बाद 51 फीसदी के साथ यूएई और 48 फीसदी इंडोनेशिया का नंबर आता है। इसके अलावा सर्वे में कहा गया कि दुनिया भर में केवल 16 फीसदी पार्टिसिपेंट्स एआई के भविष्य के प्रभाव को लेकर आशावादी हैं, जबकि 7 फीसदी लोगों का कहना है कि वे इससे खुश हैं। सबसे ज्यादा आशावादी लोग हांगकांग के हैं, जहां 33 फीसदी लोगों ने एआई को लेकर सकारात्मकता दिखाई। यूएई के 21 फीसदी एआई के विकास को लेकर उत्साहित हैं।

सर्वे से यह भी पता चला है कि अगले दशक में रोजमर्रा की जिंदगी में एआई की बढ़ती भूमिका के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण, आशावाद की तुलना में सतर्कता की ओर ज्यादा झुका हुआ है। दुनिया भर में 22 फीसदी पार्टिसिपेंट्स ने एआई के उदय के बारे में सतर्क रहने की जरुरत बताई। भारत में केवल 13 फीसदी पार्टिसिपेंट्स ने सतर्कता

व्यक्त की। इसकी तुलना में 34 फीसदी इंडोनेशियाई, 33 फीसदी पोलिश, 30 फीसदी फ्रांसीसी, 27 फीसदी सिंगापुर और 26 फीसदी स्पेनिश एआई को लेकर सतर्क हैं।

इस बीच ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स में से 17 फीसदी एआई को लेकर चिंतित हैं। सबसे ज्यादा 27 फीसदी फ्रांस, 26 फीसदी अमेरिका और 25 फीसदी ग्रेट ब्रिटेन के लोग एआई को लेकर परेशान हैं। तुलनात्मक रूप से केवल 8 फीसदी भारतीय पार्टिसिपेंट्स ने एआई को लेकर चिंता जताई है।

ब्रिटिश सांसदों ने कहा- आतंक फैलाता है पाकिस्तान, पीओके तत्काल खाली होना चाहिए

नई दिल्ली।

आतंक फैलाने के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। ब्रिटिश सांसद भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशत फैलाता और आतंकियों को पालता है। इससे तत्काल पीओके खाली करा लेना चाहिए।

हाल ही में सांसद बॉब ब्लैकमैन ने भारतीय जनता पार्टी सांसद रवि शंकर प्रसाद की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल से लंदन में मुलाकात की थी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत के साथ खड़े होने की अपील की है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है। पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान के हिस्सों में लोग हैं, जो पाकिस्तानी सैन्य शासन में भुगत रहे हैं। यहां कमान किसके हाथ में है। यहां लोकतंत्र है या जनरल हैं। और यह साफ है कि पाकिस्तान से संप्रभु भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम संदेश दें कि जम्मू और कश्मीर में भारत के हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा खत्म होना चाहिए। सैनिकों को वहां से चले जाना चाहिए और पूरे जम्मू और कश्मीर को एक प्रमुख राज्य के रूप में एकजुट किया जाना चाहिए, जैसा कि 1947 में चाहा गया था। इसके बाद हम आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लि काम करें और यह सुनिश्चित करें कि लोग घाटी की सुंदरता का मजा लें। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ब्रिटेन यात्रा मंगलवार को लंदन में संसद के दोनों सदनों और 'इंडिया हाउस' में कई बैठकों के बाद संपन्न हुई। इस दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख स्पष्ट रूप से पेश किया।

रविशंकर ने कहा, ब्रिटेन की हमारी यात्रा बहुत शानदार रही... हमारा संदेश स्पष्ट रूप से समझा गया।

उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि (आतंकवाद के खिलाफ) दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। ब्लैकमैन ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भी घेरा। उन्होंने कहा, जो राशि पाकिस्तान भेजी जा रही है, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? इसका इस्तेमाल चीनी हथियार खरीदने के लिए नहीं होना चाहिए, जो भारत पर हमले के लिए आतंकवादियों की मदद करते हैं।

टेस्ला शोरूम शुरू करने जा रहीं, वे मैन्युफैक्चरिग प्लांट लगाने की इच्छुक नहीं: कुमारस्वामी

नई दिल्ली।

अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के भारत में लॉन्चिंग का इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा है। बीते कुछ महीनों में टेस्ला इस दिशा में आगे भी बढ़ी है। टेस्ला ने भारत में अपने पहले शोरूम के लिए मुंबई में प्रॉपर्टी डील की और अलग-अलग लोकेशन पर जॉब वैकेंसीज निकाली, लेकिन अब खबर आ रही है कि कंपनी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के इच्छुक नहीं है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि एलन मस्क के स्वामित्व वाली टेस्ला भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग में रुचि नहीं रखती है। मंत्री कुमारस्वामी का यह बयान ऐसे समय आया है जब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष ध्यान दे रही है और यात्री कारों के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसके लिए सरकार ने बीते सोमवार को नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुमारस्वामी ने कहा कि टेस्ला...वे केवल शोरूम शुरू करने जा रहे हैं।

वे भारत में कारों के निर्माण में रुचि नहीं रखते हैं। हालांकि, भारी उद्योग सचिव कामरान रिजवी ने कहा कि असली इरादा हमें तब पता चलेगा जब हम आवेदन खोलेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि हुंडई, मर्सिडीज बेंज, स्कोडा और किआ जैसी कई यूरोपीय कंपनियों ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने में रुचि दिखाई है। इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि टेस्ला भारत में अपनी कारों को आयात करने और बाद में भारत में अपने शोरूम के जरिए इसे बेचने में रुचि रखती है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने संकेत दिया था कि वह भारत में निवेश करने में रुचि रखते हैं, लेकिन हाई इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर इसमें रूकावट बन रही है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। टेस्ला एक सार्वजनिक कंपनी है। यह हमारी नहीं है...जब आप भारत और यहां के लोगों की एनर्जी और हर चीज को देखते हैं और जब मैं सुनता हूं कि बीवायडी और कई अन्य कंपनियां यहां आ रही हैं और टाटा और महिंद्रा बेहतरीन कारें बना रहे हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां टेस्ला क्यों नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता. यह सिर्फ एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला शोरूम शुरू करने के लिए एक डील फाइनल की है, जिसके तहज कंपनी ने एक कॉमर्शियल टॉवर के ग्राउंड फ्लोर पर 4,000 वर्ग फुट की जगह किराए पर ली है। बताया जा रहा है कि इसका मासिक किराया 900 रुपए प्रति वर्ग फुट है। जो करीब 35 लाख रुपए प्रतिमाह के आसपास होगा। टेस्ला अगले साल अप्रैल तक आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में एंट्री कर सकती है। कुछ दिनों पहले कंपनी ने भारत में होमोलोगेशन आवेदन दाखिल किए गए थे।

एलआईसी का अदाणी को निवेशः राहुल गांधी बोले- पैसा आपका, फायदा अदाणी का

सरकारी धन से निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने का आरोप

नई दिल्ली।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एलआईसी द्वारा अदाणी समूह में किए गए 5,000 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस निवेश को आम लोगों के पैसे का निजी फायदा में उपयोग करार दिया। सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, कि पैसा, पॉलिसी, प्रीमियम आपका; सुरक्षा, सुविधा, फायदा अदाणी का। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने एलआईसी में करोड़ों आम नागरिकों के भरोसे और धन को लेकर चिंता जताई है। दरअसल, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने हाल ही में 5,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह रकम 15 साल की अवधि के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के जरिए एलआईसी से प्राप्त की गई है। यह अब तक का कंपनी का सबसे बड़ा घरेलू बॉन्ड निर्गम बताया जा रहा है।

कंपनी के अनुसार, यह निवेश 7.75 प्रतिशत सालाना की प्रतिस्पर्धी कूपन दर पर हुआ है। इस बॉन्ड को बीएसई में सूचीबद्ध किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि एपीएसईजेड की मजबूत वित्तीय स्थिति और 'एएए/स्थिर' क्रेडिट रेटिंग की वजह से यह सौदा संभव हुआ।

विपक्ष ने उठाए सवाल

राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार सार्वजनिक संस्थानों जैसे एलआईसी और एसबीआई का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रही है।

इससे न केवल आम निवेशकों के हितों को खतरा है, बल्कि सरकारी संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते हैं।

केदारनाथ धाम में भारी बारिश और बर्फबारी से यात्रा रोकी गई, श्रद्धालुओं को रास्ते में रोका

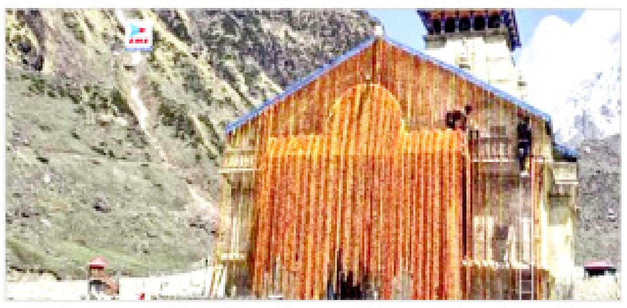

देहरादून।

उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर खतरा बढ़ गया है। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से पथरीली चट्टानों के गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके चलते चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। जानकारी अनुसार गौरीकुंड से केदारनाथ तक के 19 किमी पैदल मार्ग पर जगह-जगह भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं हुई हैं। डीडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और रास्ते के अवरोधों को दूर करने और साफ करने का काम जारी है। श्रद्धालुओं को अस्थायी शिविरों में रोका गया है, प्रशासन ने अलाव और चिकित्सा की व्यवस्था की है। मौसम विभाग ने 6 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया है, तेज गर्जना व बारिश की चेतावनी दी गई है। केदारनाथ घाटी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, इस प्रकार ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है।

बाबा केदार की नगरी बर्फ की चादर में लिपटी

केदारनाथ धाम की पहाड़ियां इस वक्त बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। धुंध व कोहरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में श्रद्धालु जहां एक ओर भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें प्राकृतिक आपदा जैसी कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने अपील की है कि मौसम को देखते हुए और अपडेट लेकर ही यात्रा करें। उत्तराखंड मौसम विभाग और प्रशासन ने चारधाम यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का अपडेट जरूर लें। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतें। प्रशासन द्वारा दी गई निर्देशों का पालन करें और सहयोग करें।

मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, देहरादून, पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ कहा गया है चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए यह समय सावधानी बरतने का है। प्राकृतिक आपदा के जोखिम के बीच सुरक्षा सर्वोपरि है। प्रशासन राहत कार्य में लगा है और जैसे ही मौसम साफ होगा, यात्रा फिर से बहाल कर दी जाएगी।

पहला कॉलम

उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने दी 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी

हर वर्ग से जुड़ा हुए हैं प्रस्ताव

देहरादून।

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के शहरी गरीबों, सरकारी कर्मचारियों, वाहन मालिकों और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा। शहरी विकास के तहत फैसला हुआ कि विभाग में कार्यरत 800 से अधिक पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित कोटे में शामिल किया जाएगा। यह फैसला सफाईकर्मियों और उनके परिवारों के लिए राहतभरा साबित होगा। इसके साथ ही पुराने वाहनों को लेकर भी कैबिनेट में बड़ा फैसला किया है। धामी सरकार ने तय किया है कि अब पुराने वाहनों को सीएनजी में बदलने की सुविधा मिलेगी। साथ ही यदि कोई वाहन स्क्रैप किया जाता है, तब वाहन स्वामी को सेमी अकाउंट के माध्यम से धनराशि प्राप्त होगी। इसके अलावा हाइब्रिड और बैट्री प्लस पेट्रोल गाड़ियों को टैक्स में छूट देने का भी निर्णय हुआ है, जो निजी वाहन मालिकों के लिए लाभकारी साबित होगा।

राज्य में अब वर्दीधारी पदों जैसे कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी के लिए एक ही लिखित परीक्षा होगी। इससे चयन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सकेगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के ढांचे में बदलाव करते हुए 15 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। इसमें 1 स्थायी और 14 अस्थायी पद शामिल हैं। साथ ही मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पद अधिसूचित किए गए हैं। पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत शेष मित्र लोटस वॉल, अराइवल प्लाज़ा, ट्री एंड रिवर कल्चर, और सुदर्शन चक्र की सांस्कृतिक स्थापत्य योजना को सीएसआर फंड के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यदि फंडिंग नहीं होती है, तब काम राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कराया जाएगा।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रात भर मिनट-टू-मिनट अपडेट लेते रहे पीएम मोदी

केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने बताया उस रात का पूरा सच

नई दिल्ली।

केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रात भर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की कोशिशों ने आतंकवाद के खिलाफ उनके संकल्प को और मजबूत किया है। भारत ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। पीएमओ में मंत्री सिंह ने बताया है कि जब 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया, पीएम मोदी रात भर पल-पल की खबर ले रहे थे। सिंह ने कहा, जब यह स्थिति आई, आपको पता है, उन्होंने अपना दौरा बीच में ही रोक दिया, रात भर मिनट-दर-मिनट निगरानी कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि घबराहट वह जानते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी तरह से विकसित संयम है। मंत्री सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ज्यादातर रात में काम करते हैं। स्थिति के तनावपूर्ण हो जाने और संघर्ष के बढ़ने को लेकर पीएम मोदी के फैसले लेने के तरीके पर कहा, उनकी वजह से, कहानी बदल गई है। क्योंकि पहली बार रक्षा बलों को अपनी व्यक्तिगत बुद्धि और विवेक के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, उनके पास दिमाग की बहुत स्पष्टता है। दूसरा, वह बहुत निर्णायक हैं और उनके फैसले भी तेजी से होते हैं।

देश के 27 राज्यों में फैला कोरोना का नया वैरिएंट, एडवाइजरी जारी

अस्पतालों में मॉक ड्रिल के आदेश, मास्क पहनना किया अनिवार्य

नई दिल्ली।

देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को 300 नए केस सामने आए थे। सबसे ज्यादा गुजरात में 108 और महाराष्ट्र में 86 मामले सामने आए। इस तरह देश में सक्रिय केसों की संख्या 4302 हो गई है। कोरोना 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपने पैर पसार चुका है। हालांकि 9 राज्यों में अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा 1373 एक्टिव केस केरल में हैं। वहीं महाराष्ट्र 510 केसों के साथ दूसरे नंबर है। कोरोना के नए वैरिएंट्स से देश में जनवरी से अब तक 44 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 37 मरीजों की मौत बीते 5 दिन में हुई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को 4 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में मरने वाला की संख्या 14 हो गई है।

इसके अलावा बीते दिन दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में भी 1-1 मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद राज्य सरकार ने देर रात एडवाइजरी जारी कर सभी हॉस्पिटल में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं केरल सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा सक्रिय केस केरल राज्य में हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को हॉस्पिटल और हेल्थ वर्कर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत राज्य के सभी हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल होगी। इस दौरान कोरोना से बचाव के तरीकों को बताया जाएगा। साथ ही सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। हॉस्पिटल में मास्क लगाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्यों के हालात पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली कोविड लहरों के दौरान बने ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड जैसी चीजों की समीक्षा हो चुकी है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

लुधियाना में उप-चुनाव, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में गायब नवजोत सिंह सिद्धू

लुधियाना।

पंजाब के लुधियाना में 19 जून को उप-चुनाव होना है। इससे पहले अपने उम्मीदवार को मजबूत करने और उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं है। सिद्धू कांग्रेस पार्टी के बड़े वक्ता है। उनका स्टार प्रचारकों में नाम न होने से चर्चाओं का दौर शुरु हो गया है। वहीं सूची में सबसे ऊपर नाम भूपेश बघेल का है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा भी उप-चुनाव में मोर्चा संभालने वाले है। किशोरी लाल ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कलाकार स्मृति ईरानी को हराया। वहीं किशोरी खुद भी लुधियाना में कांग्रेस की सेवा कर चुके है। उनका लुधियाना से जमीनी नाता है। किशोरी लाल का परिवार अभी भी लुधियाना में ही रहता है। कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशू के पक्ष में कुल 40 स्टार प्रचारक उप चुनाव में प्रचार के लिए आ रहे है। इन स्टार प्रचारकों में मुख्य चेहरे सचिन पायलट, मनीष तिवारी, अदाकार राज बबर, मोहम्मद सदीक और कन्हैया कुमार है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा, वड़िंग प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखपाल सिंह खैहरा आदि के नाम भी प्रमुख है।

राष्ट्रद्रोह वाद में कंगना रणौत को फिर नोटिस जारी, 30 जून को होगी अगली सुनवाई

आगरा।

भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ अधिवक्ता ने राष्ट्रद्रोह वाद दायर किया था। एमपी-एमएलए कोर्ट अनुज कुमार सिंह छह मई को खारिज कर दिया था। वादी अधिवक्ता ने सत्र न्यायालय में रिवीजन किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने फिर से कंगना को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। 30 जून को अगली सुनवाई होगी। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किसानों पर अभद्र टिप्पणी और स्वतंत्रता सेनानियों के अपमान का आरोप लगाकर 11 सितंबर, 2024 को कंगना रणौत के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने कंगना रणौत को पक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू मनाली और दिल्ली के पते पर तीन नोटिस भेजे थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया था। कहा था कि वादी अधिवक्ता के परिवार से किसानों के धरने में कोई मौजूद नहीं था। वाद प्रस्तुत करने से पहले भी राज्य सरकार, जिलाधिकारी से अनुमति नहीं ली थी। अगली सुनवाई 30 जून को होगी।

आज अयोध्या में राजा राम के साथ अन्य देवी-देवताओं के 5 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठ

अभीजित मुहूर्त में 101 वैदिक आचार्य की मौजूदगी में होगा कार्यक्रम

अयोध्या।

प्रभु राम की नगरी अयोध्या में स्थित राम मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन शुरू हो गया है। 5 जून को गंगा दशहरा के मौके पर अभीजित मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि मंदिर परिसर के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार और अन्य देवी-देवताओं के 5 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 3 से 5 जून के बीच संपन्न होगी। मुख्य कार्यक्रम 5 जून को किया जाएगा, जब सभी देवी देवता अपने अपने भवन में विराजमान हो जाएगें। बता दें कि इससे पहले साल 2024 में 22 जनवरी को प्रभु श्रीराम बाल स्वरूप में स्थापित हुए थे। अब दूसरी प्राण-प्रतिष्ठा में भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे। राम दरबार सहित अन्य 7 देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त कांची कामकोटि शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र सरस्वती ने निकाला था। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए गंगा दशहरा के दिन 5 जून को सर्वश्रेष्ठ बताया। इस दिन दोपहर 11 बजकर 25 मिनट पर निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात लगभग एक बजे भोग आरती संपन्न होगी। यह आयोजन वैदिक विधानों के अनुरूप तीर्थराज प्रयाग, काशी, देवप्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों से आमंत्रित 101 ऋत्विजों की उपस्थिति में संपन्न होगा। बता दें कि 5 जून को गंगा दशहरा का पावन पर्व भी है और संयोगवश यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। पूरे आयोजन में वैदिक रीति से पूजा-पाठ कराने के लिए देशभर से आए कुल 101 वैदिक आचार्य भाग ले रहे है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों की शुरुआत प्रतिदिन प्रातः 6-30 बजे से हो रही है। जिन मूर्तियों की स्थापना होगी, उनका पंचगव्य से स्नान करवाकर शुद्धिकरण किया जा चुका है। दरअसल मूर्ति को छेनी, हथौड़े से तराशा जाता है, जिससे उन पर चोट लगती है। चोट लगने की वजह से मूर्तियों से माफी मांगी जाती है। इसलिए वैदिक विधि विधान के साथ मूर्तियों का शुद्धिकरण होता है। अब 5 जून दिन गुरुवार को नियम व संयम के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होगा।

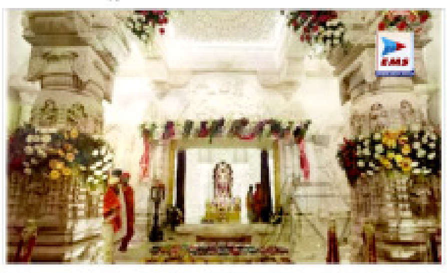

पॉक्सो कोर्ट ने धर्मांतरण गैंग की मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

अजमेर।

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने बिजयनगर रेप-ब्लैकमेल कांड में धर्मांतरण गैंग की मुख्य कड़ी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पॉक्सो कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि नाबालिग लड़की पर रोजा रखने और कलमा पढ़ने का दबाव बनाना, उनकी पसंद के कपड़े पहनने और आरोपियों के साथ जाने को मजबूर करना गंभीर प्रकृति का अपराध है। कोर्ट ने कहा कि हकीम कुरैशी ने पीड़िता को डरा-धमकाकर आरोपी सोहेल मंसूरी के साथ भेजने का षड्यंत्र रचा था। आरोपी ने कहा था कि पीड़िता के 18 साल की होने पर सोहेल लड़की को भगाकर निकाह कर लेगा। उस पर हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के लिए भी दबाव बनाया गया। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक (सरकारी वकील) प्रशांत यादव ने बताया- 5 अन्य आरोपियों ने भी जमानत याचिकाएं दायर की हैं। इनमें तीन नाबालिग और दो बालिग हैं। इन सभी की सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं। एक नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

असम में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर, 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित

गुवाहाटी।

असम में जारी भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बुधवार को और गंभीर हो गई, जिससे राज्य के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, अब तक करीब 6.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 6 और लोगों की जान चली गई है। इस वर्ष बाढ़ और भूस्खलन से मृतकों की कुल संख्या 17 पहुंच गई है।

ब्रह्मपुत्र नदी सहित सात प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने आने वाले दिनों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई है।

इसके साथ ही कुछ जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी भी दी गई है।

अतिवर्षा के कारण हैलाकांडी, श्रीभूमि, मोरीगांव, कछार, सोनितपुर, तिनसुकिया, बारपेटा, बोंगाईगांव, नलबाड़ी, ग्वालपारा, बक्सा समेत कुल 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। विस्तृत जानकारी अनुसार 69 राजस्व क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जबकि 1,506 गांव जलमग्न बताए गए हैं और इससे 6,33,114 लोग प्रभावित हुए हैं। 223 राहत शिविर में 39,746 लोग आश्रित हैं। सहायता के लिए 288 राहत वितरण केंद्र सक्रिय हैं।

एएसडीएमए अधिकारियों के अनुसार, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावितों को राशन, पीने का पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने शाहदरा जमीन पर गुरुद्वारे को दिया अधिकार, वक्फ बोर्ड की याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज करते हुए शाहदरा स्थित विवादित जमीन को गुरुद्वारे के अधिकार में दे दिया है। वक्फ बोर्ड का दावा था कि इस जमीन पर पहले एक मस्जिद 'तकिया बाबर शाह' हुआ करती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जब वहां वर्षों से एक गुरुद्वारा स्थापित है और धार्मिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं, तो वक्फ बोर्ड को अपना दावा छोड़ देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, कि यह कोई किसी तरह का ढांचा नहीं, बल्कि एक सुचारू रूप से कार्यरत गुरुद्वारा है। एक धार्मिक स्थल कार्य कर रहा है, तो उसे वहीं रहने दें। इस पर वक्फ बोर्ड की ओर से तर्क देते हुए वक्फ बोर्ड के वकील संजय घोष ने कहा, कि निचली अदालतों ने माना था कि गुरुद्वारे से पहले वहां एक मस्जिद थी। वह वक्फ की संपत्ति थी, यानी धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान की गई ज़मीन। यही वजह थी कि वक्फ बोर्ड ने इस संपत्ति की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

प्रतिवादी का तर्क और पृष्ठभूमि

प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि यह जमीन 1953 में मोहम्मद अहसान द्वारा बेच दी गई थी, और उसके बाद कब्जा भी हो गया। हालांकि, उक्त बिक्री के कोई ठोस दस्तावेज कोर्ट में नहीं पेश किए जा सके। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से अपनी याचिका वापस लेने की सलाह दी। अदालत ने दो टूक कहा कि सिर्फ यह कहना कि पहले मस्जिद थी, पर्याप्त नहीं है, जब तक कि दावे को ठोस साक्ष्यों के साथ साबित न किया जाए।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमाआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717